साप्ताहिक
Live not just breaTHE

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/16-18

दि कार्मिक पोस्ट

वर्ष : 7, अंक : 21 (प्रति बुधवार), इन्दौर 12 जनवरी 2022 से 18 जनवरी 2022 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

2015 से 2021 थे इतिहास के 7 सबसे गर्म साल, पांचवे स्थान पर रहा 2021

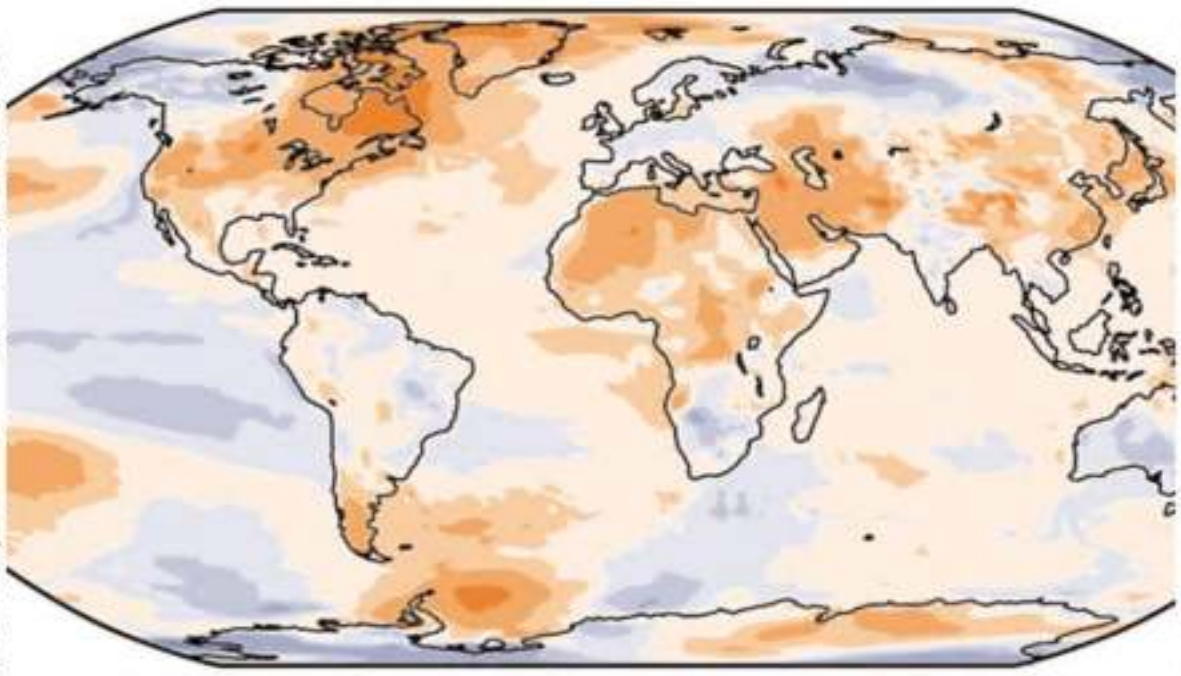

नई दिल्ली। 2015 से 2021 के बीच इतिहास के सबसे गर्म सात साल दर्ज किए गए हैं। वहीं यदि सिर्फ 2021 की बात करें तो वो इतिहास का पांचवा सबसे गर्म साल था। जब तापमान 1850 से 1900 के बीच के औसत तापमान से करीब 1.16 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया था। वहीं यदि 1991 से 2020 के औसत वार्षिक तापमान से तुलना करें तो 2021 का वार्षिक औसत तापमान 0.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। यह जानकारी यूरोपियन यूनियन की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस (सी3एस) द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट में सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक न केवल 2021 इतिहास के सबसे गर्म वर्षों में से एक था। साथ ही वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के स्तर में भी वृद्धि दर्ज की गई थी।

यदि इतिहास के सबसे गर्म वर्ष की बात करें तो 2016 काबिज है जब तापमान सामान्य से 1.32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके बाद 2020 में 1.31, 2019 में 1.28, 2017 में 1.22 डिग्री सेल्सियस, 2021 में 1.16, 2018 में 1.14 और 2015 में तापमान औसत से 1.14 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया था। देखा जाए तो 2021 में पहले पांच महीने हाल के सबसे गर्म वर्षों को तुलना में अपेक्षाकृत रूप से कम गर्म थे। वहीं जून से अक्टूबर का मासिक तापमान इतिहास में चौथा सबसे गर्म था। वहीं यदि पिछले 30 वर्षों (1991से 2020) का तापमान औद्योगिक काल से पहले के तापमान से 0.9 डिग्री सेल्सियस अधिक था। 2021 में यूरोप ने भी इतिहास के सबसे गर्म गर्मियों के मौसम का सामना किया था। जब तापमान 2010 और 2018 में गर्मियों के लगभग करीब ही था। यूरोप में 2021 के औसत तापमान को देखें तो वो 1991से 2020 के औसत से केवल 0.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। हालांकि वो 10 सबसे गर्म वर्षों में शामिल नहीं था। यूरोप के 10 सबसे गर्म साल 2000 के बाद से सामने आए हैं, जिनमें से सात सबसे गर्म वर्ष 2014 से 2020 के बीच दर्ज किए गए थे। यदि पिछले 30 सालों से तुलना करें तो 2021 में अमेरिका के पश्चिमी तट से कनाडा के उत्तर-पूर्वी हिस्सों, मध्य पूर्व और ग्रीनलैंड के साथ-साथ मध्य और उत्तरी अफ्रीका के बड़े हिस्से में तापमान औसत से ज्यादा था। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी और पूर्वी साइबेरिया, अलास्का, मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में वर्ष की शुरुआत और अंत में तापमान ला नीना के चलते सामान्य से कहीं ज्यादा कम था। इसी तरह अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश हिस्सों में भी तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया था। इस साल पूर्वोत्तर कनाडा में, वर्ष की शुरुआत और शरद ऋतु के दौरान औसत मासिक तापमान असामान्य रूप से गर्म था। वहीं जून में पश्चिमी उत्तरी अमेरिका ने असाधारण तौर पर लू का अनुभव किया था। यही वजह है कि जून में अमेरिका में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया था। जुलाई और अगस्त के दौरान अमेरिका जंगल की आग का सामना करता रहा। कैलिफोर्निया के इतिहास में दर्ज दूसरी सबसे बड़ी आग, डिक्सी फायर ने न केवल वहां व्यापक तबाही मचाई थी, बल्कि साथ ही उसके चलते हुए प्रदूषण की चपेट में हजारों लोग आ गए थे।

दावाग्नि से उत्सर्जित हुई 1850 मेगाटन कार्बन- कॉपरनिकस एटमॉस्फियर मॉनिटरिंग सर्विस (सीएएमएस) की मदद से सी3एस ने यह भी जानकारी दी है कि 2021 के दौरान ग्रीनहाउस गैसों के स्तर में भी वृद्धि दर्ज की गई थी। इस साल कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) का वार्षिक औसत स्तर इतिहास के रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गया था। इस साल सीओ2 का वार्षिक औसत स्तर करीब 414.3 पार्टस प्रति मिलियन (पीपीएम) पर पहुंच गया था। वहीं मीथेन (सीएच 4) का वार्षिक औसत स्तर लगभग 1,876 पीपीबी दर्ज किया गया था। इतना ही नहीं रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि दुनिया भर के जंगलों में लगने वाली आग से करीब 1,850 मेगाटन कार्बन उत्सर्जित हुई थी। जोकि पिछले साल की तुलना में करीब 100 मेगाटन ज्यादा है। इसके लिए विशेष रूप से साइबेरिया में लगने वाली आग जिम्मेवार माना गया है। गौरतलब है कि 2020 में इसकी वजह से करीब 1,750 मेगाटन कार्बन उत्सर्जित हुई थी। हालांकि 2003 के बाद से यह प्रवृत्ति घट रही है।

साभार - डाउन टू अर्थ

प्रदूषित नदी प्रवाह की संख्या में बढोतरी

नई दिल्ली हमारे अहम सतही जलस्रोतों का 90 प्रतिशत हिस्सा अब इस्तेमाल करने के लायक नहीं बचा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और अलग अलग राज्यों की प्रदूषण निगरानी एजेंसियों के 208 में किये विश्लेषण ने इसकी पुष्टि की है। साल 205 में वाटर ऐड की एक रिपोर्ट जारी हुई थी, जो शहरी विकास मंत्रालय, जनगणना 2011 और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों पर आधारित थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सतही पानी का 80 प्रतिशत हिस्सा प्रदूषित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की 201 8 की रिपोर्ट के मुताबिक 36 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 में नदियों का प्रवाह प्रदूषित है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 53 प्रदूषित प्रवाह हैं। इसके बाद असम, मध्यप्रदेश, केरल, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, मिजोरम, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना,मेघालय, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, तमिलनाडु, नागालैंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान, पुडुचेरी, हरियाणा और दिल्ली का नंबर आता है। 2015 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया था कि 275 नदियों के 302 प्रवाह प्रदूषित हैं जबकि साल 2018 की रिपोर्ट में 323 नदियों के 35। प्रवाह के प्रदूषित होने का जिक्र है पिछले तीन सालों में देखा गया है कि खतरनाक रूप से प्रदूषित 45 प्रवाह ऐसे हैं, जहां के पानी की गुणवत्ता बेहद खराब है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अधिसूचित किया कि नदियों में छोड़े जाने वाले परिशोधित गंदे पानी की गुणवत्ता काफी खराब है और इसमें बोयोक्रॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी (बीओडी प्रदूषण को मापने का एक पैमाना है) की मात्रा प्रति लीटर 30 मिलीग्राम है। एक लीटर पानी में 30 मिलीग्राम से अधिक बीओडी को पानी की गुणवत्ता बेहद खराब होने का संकेत माना जाता है।

साभार - डाउन टू अर्थ

नगर परिषद राऊ द्वारा सफाई कर्मचारियों को ई लर्निंग एवं आपदा प्रबंधन परीक्षण दिया गया

राऊ। नगर परिषद द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत नगर परिषद राऊ के समस्त सफाई कर्मचारियों को 3-3 ई लर्निंग कोर्स करवाये गए। जिसमे मुख्य नगर पालिम अधिकारी श्री राकेश चौहान, एस. आई.श्री हरीश व्यास व निकाय के अन्य अधिकारों मौजूद थे।

आपदा प्रबंधन परीक्षण भी दिया

नगर निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण २०२२ की मार्गदर्शिका के अनुसार आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में तमाम अधिकारी मौजूद रहे एवं कर्मचारियों ने भी गंभीरता पूर्वक प्रशिक्षण लिया।

आलीराजपुर में दो चचेरे भाइयों के शव फंदे पर लटके मिले, स्वजन ने लगाया हत्या का आरोप

आलीराजपुर (एजेंसी)। सोरवा थाना क्षेत्र के ग्राम पीथमपुर में दो चचेरे भाइयों के शव अलग-अलग जगह फंदे पर लटके मिले हैं। घटना से गांव में सनसनी फैल गई। मामले में स्वजन ने हत्या का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। पुलिस ने फिलहाल कायम किया है। जिला अस्पताल में शवों का पोस्टमार्टम करायाा गया है। पुलिस का कहना मामले की जांच की जा रही है। सोरवा थाना प्रभारी योगेंद्र मंडलोई ने बताया कि घटना मंगलवार की है। गांव के युवक राजू पिता हरलिया उम्र 22 तथा प्रवीण पिता मोगरिया 17 फंदे पर लटके मिले हैं। एक शव घर में सीढ़ियों के पास तथा दूसरा बाहर एक पेड़ पर लटका मिला। दोनों चचेरे भाई थे। जिला अस्पताल में पीएम के बाद शव स्वजन को सौंप दिए गए हैं। प्रारंभिक जांच में खुदकुशी की बात सामने आई है। हालांकि जांच के बाद स्थिति साफ हो सकेगी। जिला अस्पताल में पीएम के दौरान स्वजन और गांववालों ने घटना को लेकर आक्रोश जताया। उनका आरोप था कि युवक और किशोर खुदकुशी कर ही नहीं सकते। ऐसा कोई कारण ही नहीं था। दोनों की हत्या की गई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच करे तथा दोषियों तक पहुंचे। मौके पर मौजूद पुलिस अफसरों ने तत्परता से जांच का आश्वासन दिया है।

चार अज्ञात आरोपियों पर 10 हजार का ईनाम किया घोषित

खरगोन (संवाददाता द्वारा) पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ चौधरी ने बड़वाह में हुई घटना के 04 अज्ञात आरोपियों पर 10 हजार का उद्घोषणा जारी की है। अज्ञात आरोपियों का थाना बड़वाह में अपराध क्रमांक 18/2022 की धारा 452, 394, 397 भादवि के तहत पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया है। पुलिस अधीक्षक श्री चौधरी ने इस घटना के अज्ञात आरोपियों की धरपकड़ या बंधी बनाने में पुलिस का सहयोग करने वाले को घोषित ईनाम दिया जाएगा। जानकारी या सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

पोरवाल कास्मेटिक एण्ड जनरल स्टोर्स
नंदकिशोर कारा (नंदू बादशाह) 9303240607
अभिषेक पोरवाल 9827386742
- किराना एवं कास्मेटिक सामान
- पंतजलि प्रोडक्ट एवं संपूर्ण पूजन सामग्री
- शादी-पार्टी, बर्थडे शुभकार्यों में बेलून डेकोरेशन
माँ भगवती द्वार ३६६१ सुदामानगर ई -सेक्टर हवा बंगला मेनरोड़ इंदौर

धनोतिया ट्रेडर्स
समस्त प्रकार के पैकिंग मटेरियल के विक्रेता
132, जवाहर मार्ग, इंदौर फोन. 2349392, नि. 2349392

जहरीली हवा-हर साल 18.5 लाख बच्चों को अस्थमा का मरीज बना रहा है हवा में घुला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड

मुंबई। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दुनिया भर में हर साल 18.5 लाख बच्चों को अस्थमा का मरीज बना रहा है जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि जिस हवा में हमारे बच्चे सांस ले रहे हैं वो कितनी जहरीली हो चुकी है। इतना ही नहीं अपने बच्चों में बढ़ते अस्थमा के लिए हम स्वयं ही जिम्मेवार हैं। यह जानकारी जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के मिलकेन इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा किए अध्ययन में सामने आई है जोकि जर्नल लैंसेट प्लैनेटरी अर्थ में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं की मानें तो इसके लिए कहीं हद तक हमारी गाड़ियों से निकलने वाले धुंए और उससे होने वाले वायु प्रदूषण का नतीजा है। यह समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि उसने लॉस एंजेलिस से लेकर भारत में मुंबई तक को अपनी गिरफ्त में ले लिया है।

अपने इस शोध में शोधकर्ताओं ने लॉस एंजिल्स से लेकर मुंबई तक 13,000 से अधिक शहरों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण बच्चों में होने वाले अस्थमा के बोझ का अनुमान लगाया है। जिसके लिए उन्होंने 2000 से 2019 के बीच सामने आए अस्थमा के मामलों का विश्लेषण किया है साथ ही उन्होंने वाहनों, पावर प्लांटस और उद्योगों से होने वाले प्रदूषण और उसके प्रभाव का अध्ययन किया है। निष्कर्ष में सामने आया है कि 2019 में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होने वाले प्रदूषण से बच्चों में अस्थमा के 18.5 लाख मामले सामने आए थे। जिनमें से करीब दो तिहाई शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों में दर्ज किए गए थे, जिनका कुल आंकड़ा 12.2 लाख था। हालांकि अध्ययन में यह भी सामने आया है कि पिछले कुछ समय में भारत सहित दुनिया के अन्य शहरों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण बच्चों में होने वाले अस्थमा के मामलों में गिरावट आई थी। शोधकर्ताओं के मुताबिक इसके पीछे की वजह वायु प्रदूषण को लेकर सरकारों द्वारा उठाए गए कड़े कदम थे। विशेष रूप से अमेरिका जैसे संपन्न देशों में इसका प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक भले ही यूरोप और अमेरिकी शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया है लेकिन इसके बावजूद दक्षिण एशिया, उप-सहारा अफ्रीकी और मध्य पूर्व में हवा विशेष रूप से दूषित होती जा रही है जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि खास तौर पर दक्षिण एशिया और उप-सहारा अफ्रीका के शहरों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण बच्चों में होने वाले अस्थमा के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई थी। आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण एशिया में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण बच्चों में होने वाले अस्थमा के करीब 50 हजार मामले वर्ष 2000 में सामने आए थे वो 2019 में 81 फीसदी बढ़कर 90,400 पर पहुंच गए थे। इसी तरह उप सहारा अफ्रीका में 2000 के दौरान इन मामलों की संख्या 49,100 थी जो 2019 में 110 फीसदी बढ़कर 102,900 पर पहुंच गई थी। वहीं दूसरी तरफ उच्च आय वाले देशों को देखें तो जहां 2000 में एनओ2 के चलते बच्चों में अस्थमा के 464,800 मामले सामने आए थे जो 2019 में 27 फीसदी घटकर 340,900 पर पहुंच गए थे। कुल मिलकर 2000 में जहां बच्चों में अस्थमा के 20 फीसदी मामलों के लिए एनओ2 जिम्मेवार था, वो 2019 में घटकर 16 फीसदी पर आ गया था। इससे पहले भी किए शोध में सामने आया था कि दुनिया भर में बच्चों में सामने आए अस्थमा के करीब 13 फीसदी मामलों के लिए हवा में घुला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिम्मेवार था जबकि सबसे ज्यादा आबादी वाले 250 शहरों में यह आंकड़ा 50 फीसदी तक था। भारत जैसे देशों में यह समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। जहां दिल्ली जैसे शहर अपनी जहरीली होती हवा को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अपने निष्कर्ष के बारे में जानकारी देते हुए शोधकर्ता सूसन एनेनबर्ग का कहना है कि बढ़ता नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बच्चों में अस्थमा को बढ़ा रहा है। शहरी क्षेत्रों में यह समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। ऐसे में बच्चों को इस जहरीली हवा से बचाने के लिए हवा की गुणवत्ता में सुधार हमारी रणनीतियों का एक अहम हिस्सा होना चाहिए।

विलुप्ति की कगार पर हैं ड्रैगनफ्लाई और डैमसेलफ्लाई की 16 फीसदी प्रजातिया

न्यूयार्क। दुनियाभर में ड्रैगनफ्लाई और डैमसेलफ्लाई की 16 फीसदी प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। यह जानकारी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में सामने आई है जिसमें वैश्विक स्तर पर इन शानदार रंगीन कीड़ों की सभी 6,016 प्रजातियों का आंकलन किया गया है।

गौरतलब है कि यह पहला मौका है जब संकट ग्रस्त प्रजातियों की पहचान के लिए आईयूसीएन द्वारा जारी रेड लिस्ट में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी प्रजातियों की कुल संख्या 40,084 पर पहुंच गई है। इस रेड लिस्ट में 142,577 प्रजातियां शामिल हैं। देखा जाए तो इस नाजुक प्रजाति का होने वाला पतन दलदलों, झीलों और नदियों को होने वाले व्यापक नुकसान को भी दर्शाता है, जिसकी वजह से इन प्रजातियों पर संकट मंडराने लगा है। यह प्रजातियां इन्हीं वेटलैंडस में पनपती हैं। आईयूसीएन के अनुसार इसके लिए कहीं हद तक बिना पर्यावरण को ध्यान में रखे की जा रही कृषि और बेतरतीब तरीके से किया जा रहा शहरीकरण जिम्मेवार है। ड्रैगनफ्लाइज को वैश्विक स्तर पर हो रहे नुकसान का खुलासा करते हुए आईयूसीएन के महानिदेशक ब्रूनो ओबेर्ले ने अपने एक बयान में कहा है कि इन प्रजातियों को हो रहा नुकसान दुनिया भर में इन प्रजातियों को पनाह देने वाली आर्द्रभूमियों की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। उनके अनुसार वैश्विक स्तर पर ये पारिस्थितिकी तंत्र जंगलों की तुलना में तीन गुना ज्यादा तेजी से गायब हो रहे हैं। उनके अनुसार भले ही यह दलदली भूमियां और वेटलैंडस देखने में मनुष्य के लिए फायदेमंद न लगें, लेकिन वास्तव में यह हमें आवश्यक सेवाएं प्रदान करती हैं। यह हमें साफ पानी और भोजन देने के साथ ही दुनिया की ज्ञात दस में से एक प्रजाति को आवास प्रदान करती हैं। दुनिया के 1.21 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले यह वेटलैंडस कितने महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनसे हमें हर वर्ष हर वर्ष करीब 2,758 लाख करोड़ रुपए (37.8 ट्रिलियन डॉलर) का लाभ होता है। यह लाभ बाढ़ की रोकथाम, खाद्य उत्पादन, जल गुणवत्ता में हो रहे सुधार और कार्बन भंडारण के रूप में होता है, जबकि इकोसिस्टम के रूप में यह कितने फायदेमंद हैं इनकी गणना करना आसान नहीं है। आईयूसीएन के अनुसार दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में सभी प्रजातियों में से करीब एक चौथाई खतरे में हैं। जिसके लिए मुख्य रूप से फसलों और ताड़ के पेड़ों के लिए आद्रभूमियों और जंगलों का किया जा रहा सफाया जिम्मेवार है।वहीं मध्य और दक्षिण अमेरिका में इन ड्रैगनफ्लाइज में आ रही गिरावट के लिए प्रमुख रूप से आवासीय और व्यावसायिक निर्माण के लिए जंगलों की कटाई जिम्मेवार है। देखा जाए तो कीटनाशकों का बढ़ता प्रयोग, जलवायु परिवर्तन और अन्य प्रदूषक दुनिया भर में प्रजातियों के लिए बढ़ता हुआ खतरा हैं, यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप में ड्रैगनफ्लाइज के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। इस बारे में आईयूसीएन एसएससी ड्रैगनफ्लाई विशेषज्ञ समूह की सह-अध्यक्ष डॉ वियोला क्लॉसनिट्जर ने जानकारी दी है कि यह ड्रैगनफ्लाइज मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति के अत्यधिक संवेदनशील संकेतक हैं। साथ ही यह वैश्विक मूल्यांकन इनकी गिरावट को प्रगट करता है। उनके अनुसार इन खूबसूरत कीड़ों के संरक्षण के लिए यह जरुरी है कि सरकारें, कृषि और उद्योग विकास सम्बन्धी परियोजनाओं में इन आद्रभूमियों के पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण पर भी विचार करें।

आत्मनिर्भर भारत

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन

"उठो, जागो और तब तक नहीं रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाये।"
- स्वामी विवेकानंद

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर

रोजगार दिवस का आयोजन

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
- मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना

सुरभि जोशी, विदिशा, लाभार्थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

चंद्रबहादुर सोनी, भोपाल
लाभार्थी, प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना

मंगलेश वर्मा, नाथालसेड़ी, लाभार्थी
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

रीता सावरा, नरसेड़ा, लाभार्थी,
म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

सुनीता मेहर, रतुआ रतनपुर, लाभार्थी,
मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना

5 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए ऋण स्वीकृति एवं वितरण

मुख्य अतिथि
श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश
के कर कमलों द्वारा सम्पन्न होगा

12 जनवरी, 2022 अपरान्ह 1.00 बजे
कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, भोपाल

मुख्यमंत्री जी द्वारा हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद

सभी जिला मुख्यालयों पर रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ लेने के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में संपर्क करें

16 नवम्बर 2021 से स्वीकृत प्रकरणों में ऋण वितरण

"प्रदेश में अगले दो वर्ष में 30 लाख से अधिक स्व-रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारे प्रयासों का परिणाम है।"

ओमप्रकाश सखलेचा
मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

LIVE STREAMING
http://gov.in/mp/cmevents
दूरदर्शन एवं अन्य चैनलों
@Cmmadhyapradesh
@jansampark.madhyapradesh
@Cmmadhyapradesh
@jansamparkMP

#सशक्त_युवा_समृद्ध_एमपी

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

झंडा ऊंचा रहे हमारा अभियान की तैयारियां शुरू

इंदौर(नगर प्रतिनिधि) स्वतंत्रता दिवस के स्वर्ण जयंती महोत्सव की श्रृंखला में इस बार गणतंत्र दिवस पर संस्था सेवा सुरभि, जिला प्रशासन, नगर निगम एवं इंदौर पुलिस के सहयोग से प्रवर्तित ' झंडा इंचा रहे हमारा अभियान' 16 जनवरी से 31 जनवरी तक धूमधाम से मनाया जाएगा। रीगल तिराहे पर परंपरागत 'इंडिया गेट' एवं 'अमर जवान ज्योति' की प्रतिकृति की स्थापना रविवार 16 जनवरी को सुबह 10 बजे की जाएगी। अभियान के तहत शहर के प्रमुख स्कूलों में 16 से 31 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में वरिष्ठ समाजसेवी मुकुंद कुलकर्णी, पत्रकार कृष्णकुमार अष्ठाना, ओ.पी. कानूनगो एवं संस्था के पदाधिकारियों ने शहर के प्रमुख विद्यालयों में सम्पर्क कर बच्चों के लिए स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित विषयों पर स्पर्धाएं आयोजित करने का आग्रह किया है। संस्था सेवा सुरभि के संयोजक ओमप्रकाश नरेड़ा ने बताया कि झंडा उंचा रहे हमारा अभियान का शुभारंभ पर पर कलेक्टर मनीषसिंह, पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा, सांसद शंकर लालवानी, विधायक श्रीमती मालिनी गौड़, आकाश विजयवर्गीय, भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे एवं कांग्रेस के नगर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल भी आमंत्रित किए गए हैं। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने भी इस अवसर पर आने की स्वीकृति प्रदान की है।

मालवा-निमाड़ में बारिश-ओलों ने तोड़ी किसानों की कमर, अब खाने के लाले

इंदौर (नगर प्रतिनिधि)। अंचल में चार दिन पूर्व हुई ओलावृष्टि से फसलों को खासा नुकसान हुआ है। मंदसौर जिले के कई गांवों में तबाही का मंजर देखा सकता है। ग्राम सेदरा के किसान ने बताया कि तीन दिन तक भोजन ही नहीं किया है। उज्जैन जिले में कहीं सर्वे शुरू हो गया तो कहीं इंतजार हो रहा है। रतलाम में भी सर्वे चल रहा है। मंदसौर जिले में यूं तो लगभग 31 गांवों में नुकसान बताया गया है, पर सेदरा, करनाली और बरुखेड़ा गांवों के हर खेत में नुकसान हुआ है। मेहनत से तैयार की गई गेहूं, चना, सरसों, इसबगोल, धनिया, मैथी, लहसुन, अफीम सहित सभी फसलों को महज 10 से 15 मिनट की ओलावृष्टि व उसके बाद हुई बारिश ने 100 प्रश नष्ट कर दिया है। छोटे किसानों के सामने तो सोसायटी के कर्ज व घर में खाने-पीने का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है।

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के खेतों से ही सीधे सारा एप में इंट्री करने के निर्देश के बाद भी मंगलवार को भी पटवारी पुराने परंपरागत तरीके से ही सर्वे करते रहे। पटवारियों का कहना है कि सारा एप पर जियो टेगिंग ठीक से नहीं हो पाती है। उसमें अक्षांश देशांतर जहां मिलते हैं, वहीं खड़े होकर करना पड़ता है। इसको लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को भी बता दिया है। कलेक्टर गौतमसिंह ने कहा कि सर्वे चालू है और हमने भोपाल स्तर से अनुमति भी मांगी है कि मुआवजा वितरण प्रारंभ कर दे। पटवारियों को हो रही समस्या पर उनका कहना था कि कोई भी नई तकनीक आती है तो थोड़ी परेशानी होती ही है। मंदसौर के ग्राम सेदरा के राधेश्याम हीरालाल ने बताया कि तीन दिन भोजन ही नहीं किया। राधेश्याम ने बताया कि नौ बीघा जमीन पर तीन भाइयों का परिवार आश्रित है। यहां गेहूं, चना,लहसुन, रायडा, प्याज सभी फसलें लगाई थीं। 70-80 हजार रुपये का कर्ज पहले से ही था, अब यह फसल नहीं होगी तो और कर्ज और बढ़ जाएगा। परिवार के खानेपीने का इंतजाम कैसे होगा यह भी पता नहीं है। इस बार फसल इतनी अच्छी थी कि एक बीघा में 10 क्विंटल से ज्यादा ही गेहूं मिलते। नीमच जिले के मनासा क्षेत्र में करीब दर्जन भर गांवों में हुई नुकसानी का सर्वे हो रहा है। रतलाम जिले के जावरा व रतलाम ग्रामीण विकासखंड में फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। करीब नौ हजार की आबादी वाले बांगरोद गांव में 700 किसानों की 500 हेक्टेयर में गेहूं, चना, मैथी, लहसुन व प्याज की फसल पूरी तरह खराब हो गई। पटवारी तेजवीरसिंह चौधरी ने बताया कि जड़वासाकलां से एक किमी क्षेत्र में बांगरोद स्टेशन के पास से ग्राम नेगदड़ा तक एक पट्टी में ओले गिरे हैं। इससे वहां फसलें खराब हुई हैं। तीन दिन से हर खेत तक पहुंचकर नुकसानी का आकलन करने के बाद सारा एप में जानकारी अपलोड की जा रही है। किसान दिनेश समोतरा ने बताया कि 20 बीघा में गेहूं, पांच बीघा में मैथी की खेती की थी जो अब खराब हो गई है। अमरूद का बगीचा भी बर्बाद हो गय जिले में मंगलवार को देवास रोड स्थित कड़छा, नवेली आदि क्षेत्रों में सर्वे शुरू हो गया है, वहीं प्रभावित हमीरखेड़ी, तकवासा, कांकरिया आदि गांवों में किसान सर्वे टीम के अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं। कृषि अधिकारी कमलेश राठौर ने बताया कि जिले में चार लाख 65 हजार हेक्टेयर में रबी की बोवनी हुई है। इसमें से तीन लाख 90 हजार हेक्टेयर में गेहूं व 27 हजार हेक्टेयर में लहसुन की बोवनी हुई है। सर्वे के प्रारंभिक दौर में कुछ गांवों में 45 से 50 फीसद तक नुकसान सामने आया है। गांव टंकारिया के किसान श्याम भगत ने बताया कि उन्होंने 50 बीघा खेत में गेहूं, लहसुन, प्याज बोया था। ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश ने 30 बीघा की फसल को चौपट कर दिया है।

स्कूल व कालोनियों को किया सम्मानित

देवास (संवाददाता द्वारा)। स्वच्छता के क्षेत्र में नगर पालिक निगम के प्रयास निरंतर जारी हैं। इस दिशा में आम जनों के सहयोग को देखते हुए प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी स्वच्छता रैंकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिसमें सभी विजेता प्रतिभागियों को आयोजित स्वच्छता रेंकिंग सम्मान समारोह का आयोजन मल्हार स्मृति आडिटोरियम में किया। विशिष्ट योगदान देने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ महात्मा गांधी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर हुआ। मुख्य अतिथि देवास विधायक गायत्री राजे पवार ने विजेताओं को बधाई दी। पूर्व महापौर सुभाष शर्मा, पूर्व विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष दुर्गेश अग्रवाल, कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला, पुलिस अधीक्षक डाक्टर शिवदयाल सिंह, जिला पंचायत सीईओ प्रकाश सिंह अतिथि के रुप में उपस्थित रहे। निगम आयुक्त विशालसिंह चौहान ने अतिथियों का शाल श्रीफल भेंट कर स्वागत किया।

आयुक्त ने स्वच्छता रैंकिंग दिए जाने के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया की जानकारी दी। इस अवसर पर स्पोर्ट्स पार्क के निर्माण में अद्वितीय योगदान के लिए एसोसिएशन आफ इंडस्ट्री, सन फार्मा इंडस्ट्री और इफ्का लेबोरेटरी को सम्मानित किया गया। वैक्सीनेशन एक्टिविटी में दाऊदी बोहरा समाज व सिख समाज का भी सम्मान किया गया। नम्रता क्षीरसागर को एनिमल वेलफेयर एक्टिविटी के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक, जिंगल वीडियो, आर्ट और पोस्टर प्रतियोगिताएं भी हुई जिनके विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में सीएसआर फंड की स्वीकृति लेटर बैंकों ने अतिथियों को सौंपे। विभिन्ना व्यवसायिक प्रतिष्ठानों ने भी स्वच्छता प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, वही शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों तथा रहवासी संघ ने भी स्वच्छता प्रतियोगिता में हिस्सेदारी की। अशासकीय स्कूलों को भी पुरस्कार प्रदान किए गए। शासकीय स्कूलों में प्रथम पुरस्कार उत्कृष्ट विद्यालय, द्वितीय पुरस्कार मॉडल स्कूल और तृतीय पुरस्कार शासकीय महाकाल कालोनी को दिया गया। होटलों के सम्मान में प्रथम पुरस्कार रामाश्रय होटल, द्वितीय पुरस्कार खेड़ापति होटल और तीसरा पुरस्कार सृष्टि होटल को दिया गया। शासकीय कार्यालयों का भी पुरस्कार के लिए चयन किया गया। प्रथम पुरस्कार एसपी आफिस, द्वितीय पुरस्कार कृषि विज्ञान केंद्र और तीसरा पुरस्कार जिला पंचायत देवास को मिला। अस्पतालों में अलग अलग अस्पतालों को पुरुस्कार दिया गया। वहीं रहवासी संघ में बजरंग बली नगर को प्रथम पुरस्कार, गायत्री विहार को द्वितीय पुरस्कार तथा देवीकुलम कॉलोनी को स्वच्छता के क्षेत्र में तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। व्यवसायिक गतिविधियों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सुपर मार्केट को पहला पुरस्कार, अलंकार मार्केट ने द्वितीय पुरस्कार एवं मोदी मार्केट ने स्वच्छ देवास के लिए तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया।

तूलिका संस्था द्वारा पुरानी पेंशन बहाली संघ के जिलाध्यक्ष को पुस्तक भेंट

इंदौर संस्था तूलिका द्वारा किए जा रहे उल्लेखनीय रचनात्मक कार्य अंतर्गत तुलिका के वार्षिक अंक के प्रकाशन उपरांत संस्था की अध्यक्ष श्रीमती मणिमाला शर्मा ने मध्यप्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन के प्रांतीय प्रवक्ता एवं पुरानी पेंशन बहाली संघ के जिलाध्यक्ष श्री दिनेश परमार को तूलिका (संस्कारों की तूलिका - एक प्रयास सार्थकता की ओर) पुस्तक भेंट की ! इस अवसर पर अधिकारी कर्मचारी मोर्चे के संरक्षक श्री हरीश बोयत, पुस्तक की सम्पादक श्रीमती नमिता दुबे, सहायक सम्पादक श्रीमती जसवीर सलूजा, श्रीमती अलविन्दर कौर, श्रीमती उषा कोरान्ने आदि उपस्थित थे !!

फिर टल सकती है डीएवीवी की आफलाइन परीक्षाएँ

इंदौर। कोरोना के आसन्न खतरे के मद्देनजर डीएवीवी की आफलाइन परीक्षाएँ एक बार फिर टल सकती है। जिस तरह से महानगर में रोजाना ६०० से अधिक कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं उसके चलते यह आशंका बलवती होते जा रही है। इधर इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने भी आफलाइन परीक्षाएँ स्थगित किए जाने के संकेत दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि कोविड-१९ के बाद से ही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) सहित प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षाएँ ओपन बुक या फिर आनलाइन प्रणाली से ही करवाई गई है। इन परीक्षाओं में पास होने वालों के प्लेसमेंट में आ रही दिक्कतों को दृष्टिगत रखते हुए इस बार से पुन: आफलाइन परीक्षाएँ कराये जाने की घोषणा की गई थी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पूर्व में दिसंबर २०२१ में यूजी-पीजी की परीक्षाएँ आयोजित की थी जिन्हें छात्रों के भारी विरोध के चलते आखिरकार स्थगित करना पड़ी। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग से आफलाइन परीक्षा के निर्देश मिलने पर १८ जनवरी से एमए. एमकाम, एमएससी, एलएलबी, बीए एलएलबी की परीक्षाएँ आयोजित की जा रही है। इसके लिए बकायदा टाइमटेबल भी घोषित कर दिये गये हैं। दूसरी ओर कोरोना के ओमीक्रान वेरिएंट के सामने आने और महानगर में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए एक बार फिर विद्यार्थी संगठनों ने आफलाइन परीक्षाएँ कराये जाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यही वजह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने भी परीक्षाएँ आयोजित करने को लेकर असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई है। दूसरी ओर जब इस संबंध में इस प्रतिनिधि ने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से एक अनौपचारिक वार्ता के दौरान इस संबंध में सवाल किया तो उन्होंने भी स्थिति का आकलन कर निर्णय लेने और आफलाइन परीक्षाएँ पुन: स्थगित किए जाने के संकेत दिये हैं। देखना यह है कि शासन इस संबंध में क्या निर्णय लेता है।

आरटीपीसीआर कराने पर ही हो रही पुष्टि

इंदौर (नगर प्रतिनिधि)कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इस बार दिक्कत यह है कि ज्यादातर मामलों में रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना की पुष्टि नहीं हो रही। पुष्टि के लिए आरटीपीसीआर जांच करवाना पड़ रही है। डाक्टरों के मुताबिक दूसरी लहर के मुकाबले इस बार वायरस लोड बहुत कम है। यही वजह है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना की पुष्टि नहीं हो रही। जब तक व्यक्ति आरटीपीसीआर जांच करवाता है तब तक वह कई लोगों के लिए कोरोना वाहक बन चुका होता है। लैब संचालकों के मुताबिक इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं। सामान्य रूप से सीटी वैल्यू 30 से ज्यादा होने पर रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना की पुष्टि नहीं होती। कोरोना की पुष्टि के लिए दो तरह की जांच होती है। आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट आने में कई-कई घंटे लग जाते हैं जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट कुछ ही मिनट में मिल जाती है। यही वजह है कि तुरंत रिपोर्ट के लिए लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर में यह जांच बेमानी साबित हो रही है। दरअसल बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें रैपिड रिपोर्ट निगेटिव आने के बावजूद व्यक्ति संक्रमित मिल रहा है। लैब संचालकों के मुताबिक जांच के लिए लैब पहुंचने वालों में गंभीर लक्षण वाले मरीज बहुत कम हैं। जिन लोगों में गंभीर लक्षण नहीं हैं उनकी रैपिड रिपोर्ट निगेटिव आ रही है।

किसान मोर्चा की संभागीय बैठक 13 जनवरी को इंदौर में

इंदौर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष व इंदौर संभाग प्रभारी श्री राजेन्द्रसिंह राजपूत व प्रदेश मंत्री व इंदौर संभाग सह प्रभारी रवि रावलिया ने बताया कि किसान मोर्चा इंदौर संभाग की बैठक 13 जनवरी 2022 को प्रात: 11 बजे बरसाना गार्डन, बिचोली मर्दाना बायपास चौराहा पर आयोजित की गई है। बैठक में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अनिल सुखदेव बोर्डे व किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दर्शनसिंह चौधरी मार्गदर्शन देने हेतु विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

स्वामी विवेकानंद जयंती पर आज होंगे 35 हजार युवा लाभांवित

इंदौर राज्य शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस पर आज रोजगार दिवस मनाया जायेगा। रोजगार दिवस के अवसर पर इंदौर के लगभग 35 हजार युवाओं को लाभांवित किया जायेगा। इन युवाओं को स्वरोजगार के लिये 206 करोड़ रूपये से अधिक की राशि उपलब्ध कराई जायेगी। इसके लिये उन्हें शासन की विभिन्न रोजगारमूलक योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृति तथा वितरण पत्र सौपे जायेंगे। मुख्य कार्यक्रम आज दोपहर एक बजे स्थानीय जाल सभागृह में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुये 100 से अधिक युवाओं को स्वीकृति तथा वितरण पत्र दिये जायेंगे। शेष युवाओं को बैंकों के माध्यम से उसी दिन स्वीकृति तथा वितरण पत्र प्राप्त होंगे।

कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने सभी संबंधित विभागों और बैकों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे प्रत्येक हितग्राही से संपर्क करें। उन्हें 12 जनवरी को ही बैंक शाखाओं में बुलाकर स्वीकृति तथा वितरण पत्र सौंपे। इस कार्य को विशेष प्राथमिकता दी जाये। उन्होंने बताया कि रोजगार दिवस पर इंदौर जिले में 34 हजार 937 युवाओं को 206 करोड़ से अधिक राशि की स्वीकृति तथा वितरण पत्र सौपे जायेंगे। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने बताया कि जिले में उक्त युवाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथकर विक्रेता योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आदि के तहत लाभांवित किया जा रहा है। रोजगार दिवस पर कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के लिये अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये है। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाये। रोजगार मेला का मुख्य कार्यक्रम भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हाल (मिंटो हाल) में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में होगा। इस समारोह का इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सीधा प्रसारण भी होगा। उन्होंने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों और राज्य तथा केंद्र सरकार की कोविड गाइडलाइन के दृष्टिगत सभी प्रोटोकाल का पालन किया जाए। मुख्य समारोह के सीधे प्रसारण के दृष्टिगत भी कार्यक्रम में सुसंगत व्यवस्था की जाए। स्व-रोजगार की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत विभिन्न विभागों एवं बैंको के माध्यम से कई स्व-रोजगार योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंडअप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आदि प्रमुख योजनाएँ संचालित की जा रही है। शासन की मंशानुरूप स्व-रोजगार, रोजगार से जुड़ी सभी योजनाओं में शत-प्रतिशत स्वीकृति, मेला आयोजन से पूर्व सुनिश्चित की जाए।

स्कूलों में नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम

इंदौर (नगर प्रतिनिधि)। कोरोना संक्रमण का असर इतना बढ़ गया कि शासन को सभी तरह के बड़े आयोजनों को प्रतिबंध करने का निर्णय लेना पड़ा। इसी निर्णय का असर आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर होने वाले आयोजनों पर भी पड़ेगा। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति नगण्य होने के बावजूद वहां केवल झंडावंदन होगा, किसी तरह का सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रम नहीं हो सकेगा।

गणतंत्र दिवस पर सामाजिक व राजनीतिक दल देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम कराते हैं। रीगल चौराहा पर भी सालों से गणतंत्र दिवस को लेकर कार्यक्रम होते हैं। इस बार कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार रहा है, जिसका असर आमजनों के साथ व्यापारियों पर भी पड़ रहा है। हालांकि, मलमास होने के कारण बाजारों में ग्राहकी लगभग कम होने लगी है। जैसे-तैसे सुरक्षा के भय को लेकर व्यापारी कारोबार कर रहे हैं। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि अगले सप्ताह से तक मरीजों की संख्या में अपेक्षाकृत कमी नहीं आई तो गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रम का उत्साह खत्म हो जाएगा। बताया जाता है कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रम औपचारिक बनकर रह जाएगा। केवल झंडावंदन कार्यक्रम ही आयोजित हो सकेंगे।

कोरोना की नई दवा मोल्नुपिरावीर नहीं बनाना चाहती प्रदेश की कंपनियां

इंदौर (संवाददाता द्वारा)। कोरोना की तीसरी लहर प्रदेश में दस्तक दे चुकी है। अब तक प्रदेश में कोरोना की नई दवा मोल्नुपिरावीर की उत्पादन नहीं हो रहा। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच भी दवा कंपनियों की रुचि इस दवा का उत्पादन करने में नहीं है। दरअसल दवा कंपनियां मान रही है कि प्रदेश और देश में दवा की ज्यादा जरुरत नहीं पड़ेगी। एक दवा कंपनी ने अनुमति मांगी तो है लेकिन वह भी दवा का उत्पादन निर्यात के लिए करेगी। बाजार में भी फिलहाल दवा की मांग न के बराबर है।

बीते वर्ष कोरोना की दूसरी लहर के दौरान इंदौर और पूरे प्रदेश में आक्सीजन और जरुरी दवा-इंजेक्शन की खांसी किल्लत देखने को मिली थी। काफी समय बाद जरुरी दवाओं का प्रबंध करने के लिए प्रदेश सरकार ने फेबिपिरावीर टेबलेट और पोसाकोनाजोल इंजेक्शन के निर्माण की अनुमति इंदौर की दवा कंपनियों को दी थी। मई 2021 में इंदौर में दवाओं का उत्पादन शुरू हुआ। यहां से अन्य प्रदेशों में भी दवा भेजी जा सकी। कोरोना के ताजा दौर के पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन और सरकार ने उपचार के नए निर्देश जारी किए हैं। उपचार में काम आने वाली मोल्नुपिरावीर नामक दवा चार जनवरी को देश में लांच हो चुकी है। फिलहाल इस दवा का उत्पादन हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई की कुछ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां कर रही है। दवा बनाने के लिए कच्चा माल आपूर्ति करने वाले बेसिक ड्रग डीलर्स एसोसिएशन ने बीते दिनों प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर दवा निर्माण की अनुमति प्रदेश की कंपनियों को देने की मांग की। हालांकि दवा निर्माता कंपनियां ही बेसिक ड्रग डीलर्स एसोसिएशन की मांग के इत्तेफाक नहीं रख रही। इंदौर की एक दवा कंपनी ने मोल्नुपिरावीर के निर्माण की अनुमति मांगी तो है लेकिन सिर्फ निर्यात के लिए। किसी भी नई दवा के निर्माण के लिए लायसेंस दिल्ली से ही जारी होता है। कोरोना के दूसरे दौर में तमाम जरुरी दवाओं को निर्माण करने वाली कंपनी के डायरेक्टर अभिजीत मोतिवाले के अनुसार मोल्नुपिरावीर नई दवा है इसलिए केंद्रीय एफडीए ही इसके निर्माण की अनुमति देगा। बीते वर्ष ऐन वक्त पर कोरोना में दवा उत्पादन करने वाले कई निर्माताओं को अच्छा खासा घाटा उठाना पड़ा, क्योंकि दवा का निर्माण शुरू होने बाद उसकी मांग घट गई ऐसे में लाइसेंस से लेकर उत्पादन यूनिट व कच्चे माल पर खर्च भी उन पर भारी पड़ा। उस दौर में क्योंकि लोगों को परेशानी ज्यादा थी इसलिए हम जैसे कुछ निर्माताओं ने बिना व्यापारिक जोड़-घटाव किए उत्पादन व आपूर्ति की। इस साल कोरोना के प्रकोप से अस्पताल में भर्ती होने व गंभीरता की स्थिति दिख नहीं रही। ऐसे में कोई भी स्थानीय निर्माता दो लाख रुपये की फीस देकर ऐसा ड्रग लायसेंस नहीं लेना चाहेगा जिसकी मांग नजर नहीं आ रही।

न्यायालय के प्रवेश द्वार पर वैक्सीन लगाने की व्यवस्था हो

रतलाम (संवाददाता द्वारा)। कोरोना संकमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष अभय शर्मा ने प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश राजेशकुमार गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वालों लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगने की जांच कराने व न्यायालय के प्रवेश द्वार पर ही वैक्सीन लगाने की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित करने की मांग की है।

ज्ञापन में बताया गया है कि देश भर में कोरोना संक्रमण के रोगियों की संख्या दिनों-दिन बढ़ रही है। जिला न्यायालय में पक्षकारों का आना-जाना लगा रहता है। न्यायालय परिसर में आने वाले लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगे हैं, यह चेक करने की कई व्यवस्था नहीं है। गत दिनों पुलिस ने कोरोना संक्रमित आरोपित को न्यायालय में पेश किया था। ऐसे में कोर्ट में कार्य कर रहे न्यायाधीश, कर्मचारी, अभिभाषकों के साथ ही उनके परिवार को भी खतरा उत्पन्न होने की आशंका है। जिले में पदस्थ अधीनस्थ न्यायाधीशों को निर्देशित किया जाए कि अति आवश्यक होने पर ही पक्षकार को न्यायालय बुलाया जाए। प्रवेश द्वार पर जिम्मेदार व्यक्ति की नियुक्ति की जाए, जो यह सुनिश्चित करें कि न्यायालय में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को वैक्सीन के दोनों डोज लगे हैं या नहीं। अध्यक्ष शर्मा ने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति बगैर काम के न्यायालय परिसर में न आए।

कपास की नीलामी शुरू

रतलाम। महू रोड स्थित कृषि उपज मंडी में बुधवार से कपास की नीलामी भी प्रारंभ की गई। पहले दिन मंडी में डीसीएच-32 कपास की 18 क्विंटल की आवक हुई। मंडी के सहायक सचिव सत्यनारायण गोयल की उपस्थित में नीलामी प्रारंभ की गई। इसके बाद व्यापारियों ने बोली लगाकर खरीदी शुरू की। पहले दिन कपास 12 हजार 730 रुपये से 13 हजार 100 रुपये क्विंटल बिका।

19 वर्षों में बेंगलुरु, पुणे और सूरत में पीएम 2.5 के कारण हुई 200 फीसदी अधिक मौतें

बैंगलुरु। पिछले 19 वर्षों में बेंगलुरु, पुणे और सूरत में पीएम 2.5 के कारण होने वाली मौतों में 200 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। पता चला है कि बेंगलुरु में वर्ष 2000 में जहां 2,090 लोगों की मौत के लिए पीएम 2.5 जिम्मेवार था। वहीं 2019 में यह आंकड़ा करीब 255 फीसदी की वृद्धि के साथ बढ़कर 7,410 पर पहुंच गया था। इसी तरह पुणे में भी इस अवधि के दौरान पीएम 2.5 के कारण होने वाली मौतों में 225 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी जब यह आंकड़ा 1,710 से बढ़कर 5,550 पर पहुंच गया था। वहीं सूरत में भी इस दौरान पीएम 2.5 से मरने वालों के आंकड़े में 202 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी, जब मरने वालों का आंकड़ा 1,540 से बढ़कर 4,650 पर पहुंच गया था। यह जानकारी हाल ही में जर्नल लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में प्रकाशित एक शोध में सामने आई है।

इसी तरह इंदौर में भी इस दौरान पीएम 2.5 के कारण होने वाली मौतों में भी करीब 181 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी। वहीं भोपाल में यह आंकड़ा 155 फीसदी, हैदराबाद में 130 फीसदी, मुंबई में 117 फीसदी, चेन्नई में 115 फीसदी, नागपुर में 101 फीसदी, पटना में 81 फीसदी, अहमदाबाद में 80 फीसदी, दिल्ली में 76 फीसदी, वडोदरा में 76 फीसदी, जयपुर में 73 फीसदी, कोयंबटूर में 72 फीसदी, लखनऊ में 66 फीसदी, चंडीगढ़ में 64 फीसदी, धनबाद में 58 फीसदी, आगरा में 54 फीसदी, कोलकाता में 47 फीसदी, कानपुर में 36 फीसदी, हैदराबाद में 33 फीसदी और कोच्चि में 24 फीसदी था। वहीं यदि 2019 के दौरान पीएम2.5 के कारण होने वाली कुल मौतों की बात करें तो वो दिल्ली में सबसे ज्यादा 29,900 थी। वहीं कोलकाता में 21,380, मुंबई में 16,020, बेंगलुरु में 7,410, चेन्नई में 7,190, हैदराबाद में 6,460, अहमदाबाद में 5,970 और पुणे में 5,550 लोगों की जान पीएम 2.5 ने ली थी। वहीं 2000 से 2019 के बीच पीएम 2.5 के स्तर में हुई वृद्धि की बात करें तो सबसे ज्यादा पुणे में 116 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी, जबकि इंदौर में 92 और भोपाल में 89 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी। वहीं बेंगलुरु में 82 फीसदी की वृद्धि रिकॉर्ड की गई थी। इस दौरान अध्ययन किए गए प्रमुख भारतीय शहरों में अकेला चंडीगढ़ ही ऐसा शहर था जहां इस दौरान पीएम2.5 के स्तर में 2.3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी। इस दौरान अध्ययन किए गए प्रमुख भारतीय शहरों में अकेला चंडीगढ़ ही ऐसा शहर था जहां इस दौरान पीएम2.5 के स्तर में 2.3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं यदि देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो इस दौरान पीएम2.5 में 11 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी, जबकि मुंबई में 75 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी। अध्ययन के अनुसार यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो 2019 में शहरों क्षेत्रों में होने वाली करीब 18 लाख मौतों के लिए पीएम2.5 जिम्मेवार था। इतना ही नहीं इन शहरों में रहने वाले करीब 250 करोड़ लोग ऐसी हवा में सांस लेने को मजबूर हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इतना ही नहीं शोधकर्ताओं का मानना है कि दुनिया के शहरों

में हर एक लाख पर होने वाली 61 मौतों के लिए बढ़ता पीएम 2.5 जिम्मेवार था।अपने इस शोध में शोधकर्ताओं ने 2000 से 2019 के बीच दुनिया के 13,000 से अधिक शहरों का अध्ययन किया है, जिसमें उन्होंने पीएम 2.5 के स्तर और उससे होने वाली मौतों का विश्लेषण किया है। शोध के अनुसार दुनिया में पीएम 2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय सीमा से करीब सात गुना अधिक था। यदि क्षेत्रीय आधार पर देखें तो जहां इस अवधि के दौरान अफ्रीका के कुछ हिस्सों में प्रदूषण के स्तर में 18 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं यूरोप में यह गिरावट 21 फीसदी और अमेरिका (उत्तरी और दक्षिण) में 29 फीसदी दर्ज की गई थी। जबकि दूसरी तरफ भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया के शहरी क्षेत्रों में इस दौरान प्रदूषण के स्तर में 27 फीसदी की वृद्धि रिकॉर्ड की गई थी। नतीजन दक्षिण पूर्व एशियाई शहरों में इस दौरान पीएम 2.5 के कारण होने वाली मौतों में करीब 33 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी। जब प्रति एक लाख लोगों में पीएम 2.5 के कारण होने वाली मौतों का आँकड़ा 63 से बढ़कर 84 पर पहुंच गया था। इसी तरह हाल ही में जर्नल लैंसेट में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि हर साल हवा में मौजूद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 18.5 लाख बच्चों को अस्थमा का मरीज बना रहा है। शोधकर्ताओं के मुताबिक भले ही यूरोप और अमेरिकी शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया है लेकिन इसके बावजूद दक्षिण एशिया, उप-सहारा अफ्रीकी और मध्य पूर्व में हवा विशेष रूप से दूषित होती जा रही है जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि खास तौर पर दक्षिण एशिया और उप-सहारा अफ्रीका के शहरों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण बच्चों में होने वाले अस्थमा के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई थी। ऐसे में यह जरुरी है कि हवा में तेजी से घुलते इस जहर को रोकने के लिए जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाएं। यह न केवल सरकारों की बल्कि हमारी अपनी भी जिम्मेवारी है कि हम इस बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने में सरकार की मदद करें। क्योंकि हवा में घुलता यह जहर हमें हर पल बीमार करता जा रहा है, जिसका असर हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा।

साभार - डाउन टू अर्थ

किसानों के पास ही है मौसम में आ रहे परिवर्तन को रोकने का नुस्खा, करने होंगे ये काम

हरियाणा। दुनिया भर में किसानों को गर्म होती जलवायु का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी खाद के रूप में उपयोग होने वाले पोषक तत्वों के प्रदूषण को बढाती है, साथ ही मौसम की अवधि पर भी इसका असर पड़ता है। लेकिन अब पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के साथ-साथ, मिट्टी की ऊपरी सतह की उर्वरा शक्ति को बढ़ा कर दोहरी फसल पैदा कर आय को भी बढ़ाया जा सकता है।

यह पेन स्टेट एग्रोइकोलॉजिस्ट की अगुवाई में शोधकर्ताओं की एक टीम का निष्कर्ष है। टीम ने इन प्रथाओं को अपनाने से इनका कृषि उत्पादन और पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन किया। कृषि विज्ञान महाविद्यालय में फसल उत्पादन, पारिस्थितिकी के सहयोगी प्रोफेसर हीथर कार्स्टन के मुताबिक यह शोध महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कृषि में उर्वरकों के उपयोग से, गर्म परिस्थितियों के चलते खाद से अमोनिया का वाष्पीकरण बढ़ जाएगा और लगातार अधिक खतरनाक तूफान बढ़ेंगे। जिससे अधिक घुलनशील फास्फोरस का पवाह होगा। फसल वाले खेतों से नाइट्रोजन और फास्फोरस के नुकसान को सीमित करने के लिए नई रणनीतियों की आवश्यकता है। अपने निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, शोधकर्ताओं ने अमेरिकी कृषि विभाग के कृषि अनुसंधान सेवा के एक कृषि इंजीनियर सी. एलन रोट्ज़ द्वारा विकसित एकीकृत फार्म सिस्टम मॉडल का उपयोग करके कृषि प्रबंधन रणनीतियों को अपनाया। रणनीतियों को पेन स्टेट के रसेल ई. लार्सन कृषि अनुसंधान केंद्र में लंबे समय से चल रहे डेयरी क्रॉपिंग सिस्टम प्रयोग द्वारा तैयार किया गया था। उस सिमुलेशन ने वैज्ञानिकों को फसल की पैदावार, चारा उत्पादन, नाइट्रोजन की हानि, तलछट क्षरण और फास्फोरस के घुलनशील नुकसान, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, जीवाश्म ऊर्जा के उपयोग और उत्पादन लागत पर प्रभावों को निर्धारित करने में सक्षम बनाया। हाल ही में कृषि प्रणालियों में प्रकाशित निष्कर्षों में शोधकर्ताओं ने बताया कि ऊपरी सतह में खाद डालकर उर्वरा शक्ति को बढ़ा कर दोहरी फसल पैदा करने से नाइट्रोजन के होने वाले कुल नुकसान को 12 से 18 फीसदी और फास्फोरस के कुल नुकसान को 16 से 19 फीसदी तक कम कर दिया। उन्होंने देखा कि इन रणनीतियों को अपनाने से घुलनशील फास्फोरस अपवाह में अनुमानित वृद्धि और बढ़ते तापमान और अधिक वर्षा के कारण अमोनिया उत्सर्जन को कम करके भविष्य की जलवायु में होने वाले बदलाव को कम करने और निपटने का दृष्टिकोण प्रदान करता है। कार्स्टन ने बताया कि इन लाभों को कुल कृषि-उत्पादन लागत को बनाए रखने से हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा किसानों के बीच दोहरी फसल में रुचि बहुत बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि किसान महसूस कर रहे हैं कि उनके पास लंबी अवधि का मौसम है और वसंत ऋतु में अधिक वर्षा होती हैं, जो किसी भी काम को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। कार्स्टन ने कहा हमारे नतीजे बताते हैं कि भविष्य में इन रणनीतियों को अपनाने से कृषि से पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है। यह शोध %एग्रीकल्चरल सिस्टम% नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008